



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 2014/वैशाख 22, 1936

No. 115]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 2014/VAISAKHA 22, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2014

विषय : रूस और जापान में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच शुरूआत के संबंध में।

सं.14/6/2014-डीजीएडी.—यतः, मैसर्स, आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार एक याचिका रूस और जापान (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित थैलिक एनहाइड्राइड (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच प्रारंभ करने के लिए दायर की है और प्राधिकारी से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण करने का अनुरोध किया है। भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड ने संबद्ध देशों में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाठन के संबंध में संगत सूचना/आंकड़े प्रदान कराए हैं।

2. और यतः, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि संबद्ध देशों में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के; घरेलू उद्योग को क्षति के; और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं जो पाटनरोधी शुल्क की जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाठन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की जांच करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कथित पाटन की अवस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि उदग्रहित की गई तो, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा एक पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हैं।

घरेलू उद्योग एवं आधार

3. यह याचिका मैसर्स आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही संबद्ध देशों में इस उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातकर्ता के साथ कोई संबंध है, यह कि भारत में इस संबद्ध वस्तु के तीन अन्य उत्पादक भी हैं, जिनके नाम हैं, मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड और एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड, परंतु एशियन पेंट्स इस उत्पाद का उत्पादन प्राथमिकतः अपनी ग्राही खपत के लिए करता है; यह कि रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने उनकी याचिका का समर्थन किया है; यह कि याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान इस वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 87 प्रतिशत उत्पादन है और यह कि इसलिए यह याचिका उनके आधार को पूरा करती है तथा याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं। प्राधिकारी ने उपर्युक्त तथ्यों तथा इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रथमदृष्टया साक्ष्यों की जांच करने के पश्चात यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और यह याचिका प्रमुख नियमों के अंतर्गत बने नियम 5 में उल्लिखित शर्तों में आधार के मानदंड को पूरा करती है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "थैलिक एनहाइड्राइड" है जिसका व्युहाणु सूत्र "सी८एच४ओ३" है। पीएएन या पीए के रूप में भी उल्लिखित, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड का अजलेय (एनहाइड्राइड) है और वाणिज्यिक रूप से इसका उत्पादन आर्थोजाइलीन या नेफथालीन का कैटालिटिक आक्सीकरण करके किया जाता है। यह एक रंगहीन ठोस है, इसे विविध रूप में थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, थैलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम), थैलिक एसिड एनहाइड्रस, थैलिक एनहाइड्रड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि नामों से भी जाना जाता है। इस उत्पाद का उत्पादन केवल एक ग्रेड में किया जाता है। जहां तक विभिन्न अनुप्रयोगों का संबंध है, इसके भेदकरणीय विभिन्न रूप नहीं हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः थैलेट ईस्टर्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो प्लास्ट्री साइजर्स के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टिक उद्योग में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन मध्यवर्ती है। इसका प्रयोग पालिएस्टर रेजिन, पेंट्स एवं लैकर्स में प्रयोग किए जाने वाले अल्काइड रेजिन्स, अनसैचुरेटेड पालिएस्टर रेजिन्स, पालिएस्टर पालिओल्स रंग और पिगमेंट्स, हैलोजिनेटिड एनहाइड्राइड्स, पोलिईथरीयाइल्ड रेजिन्स, आइसोटोनिक एनहाइड्राइड, कीटाणु रोधी आदि जैसे उत्पादों को बनाने के लिए भी किया जाता है।

5. थैलिक एनहाइड्राइड एक कार्बनिक रसायन है जिसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्षक संख्या 29173500 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु, जिसका भारत में कथित रूप से उत्पादन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान ही है। ग्राहक उनका प्रयोग बदल-बदल कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्राधिकारी ने, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ यह विचार किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु दोनों "समान वस्तु" के रूप में मानते हैं।

संबद्ध देश

7. वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त देश रूस और जापान है।

सामान्य मूल्य

8. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि संबद्ध देशों की घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के संबंध में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के और संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की कीमत सूची या कुटेशन भी प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे परंतु वे संबद्ध देशों की घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की कीमत का कोई भी साक्ष्य/जानकारी प्राप्त करने में असफल रहे। अतः, याचिकाकर्ताओं ने रूस और जापान के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

निर्यात कीमत

9. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों के संबंध में निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया है। याचिकाकर्ताओं ने निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन और पत्तन व्यय के कारण कीमत समायोजन की अनुमति प्रदान की है।

पाटन मार्जिन

10. याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से पर्याप्त रूप से अधिक है, जिससे प्रथमदृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों में उदभूत अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है जो पाटनरोधी जांच को प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. याचिकाकर्ताओं ने पाटित आयातों की संवर्धित मात्रा के रूप में कथित पाटन, कीमत अधोदहन, कीमत निग्रहण के परिणामस्वरूप हो रही क्षति के संबंध में और घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, मालसूची, लाभप्रदता, लगाई गई पूंजी पर अर्जन और नकदी प्रवाह में गिरावट के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद पर वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक अर्जन सहन करना पड़ा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा सहन की जा रही क्षति के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है जो पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01/01/2013 से 31/12/2013 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल 2011-मार्च, 2012, अप्रैल 2012-मार्च 2013 और जांच की अवधि शामिल है।

सूचना प्रस्तुत करना

13. सम्बद्ध देशों के निर्यातकों तथा उनकी सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से अधोलिखित समय-सीमा के अंदर सभी संगत जानकारी दर्ज करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग में इस जांच से संबंधित संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। यह सूचना/प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित को प्रस्तुत की जाएगी।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा नं .240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित किसी सूचना को लिखित रूप में इस तरह से प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

16. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुतिकरण (इससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों से इसे दो पृथक सेटों में, यदि इसके किसी भाग पर "गोपनीयता" का दावा किया जाता है, फाइल किया जाना अपेक्षित है:-

(क) एक सेट गोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो, और

(ख) एक अन्य सेट अगोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो।

18. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" की प्रस्तुति को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में स्पष्टतः चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना की गई प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में समझी जाएगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुति का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करे। दोनों संस्करणों की सॉफ्ट प्रति भी प्रत्येक के पांच (5) सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

19. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं समाविष्ट होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हों और/अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाय करने वाला गोपनीय के रूप में दावा करता हो। सूचना जिसकी प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है, के साथ एक उचित कारण विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

20. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका सम्भव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

21. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

23. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. प्राटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.एस.दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2014

Sub: Initiation of anti-dumping duty investigation in respect of the imports of Phthalic Anhydride originating in or exported from Russia and Japan –reg.

No.14/6/2014-DGAD.—Whereas M/s IG Petrochemicals Limited and M/s Thirumalai Chemicals Ltd have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti dumping duty investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Russia and Japan (hereinafter also referred to as the subject countries) and requested the Authority for levy of anti dumping duties on the subject goods. M/s IG Petrochemicals Limited and M/s Thirumalai Chemicals Ltd, representing the Domestic Industry in India of the subject goods have provided relevant information/data on the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

2. And whereas, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry; and the causal link between the alleged dumping and injury, exists to justify initiation of anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates anti dumping investigation into the alleged dumping of the subject goods from the subject countries, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s IG Petrochemicals Limited and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. The petitioners have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or importer of the product in the subject countries; that there are three more producers of the subject goods in India, namely, Mysore Petrochemicals Ltd., S I Group India Ltd. and Asian Paints India Limited but Asian Paints primarily produces the product for its captive consumption; that as per information available on record, that Mysore Petrochemicals Ltd has supported their petition; that production of the petitioner companies in the Period of Investigation accounts for 87% of the total Indian production and that the petition, therefore, satisfies standing and petitioners constitute domestic industry within the meaning of the Rules. The Authority, after examining the above facts and prima facie evidence given by the petitioners in this regard, determines that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 of the Anti Dumping Rules, and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present investigation is “Phthalic Anhydride”, having molecular formula ‘C₈H₄O₃’. Phthalic Anhydride, also referred as PAN or PA, is an anhydride of Phthalic Acid, and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colourless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. The product is produced only in one grade. As regards different applications, it does not have distinguishable different types of forms. It is mainly used in the production of phthalate esters, which functions as plasticizers. It is an important chemical intermediate in plastic industry. It is also used in making of the products like Polyester Resins, Alkyd Resins used in paints and lacquers, Unsaturated Polyester Resins, Polyester Polyols, Dyes and Pigments, Halogenated Anhydrides, Polyetherimide Resins, Isatonic Anhydride, Insect Repellents etc.

5. Phthalic Anhydride is an organic chemical classified under Customs Sub-Heading No. 29173500 under the Custom Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

6. The petitioners have claimed that the subject goods, which are being allegedly dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority, for the purpose of the present investigation, has considered that the product produced by the domestic industry is comparable to the product imported from the subject countries in terms of essential product characteristics such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. The Authority treats the subject goods produced by the domestic industry as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject Countries

7. The countries involved in the present investigation are Russia and Japan.

Normal Value

8. The petitioners have claim that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries and also price lists or quotations of producers of subject goods in subject countries but they failed to get any information/evidence of the price of the subject goods in the domestic market of subject countries. The petitioners have, thus, constructed the normal value for Russia and Japan on the basis of facts available.

Export Price

9. The petitioners have claimed export prices in respect of the subject countries on the basis of data obtained from the DGCIS. The petitioners have allowed price adjustments on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, commission and port expenses to arrive at the net export price.

Dumping Margin

10. The petitioners have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped into India to justify initiation of anti dumping investigation.

Injury and Causal Link

11. The petitioners have furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price suppression and decline in capacity utilization, market share, inventories, profitability, return on capital employed and cash flow of the domestic industry. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investment on the product under consideration. There is sufficient prima facie evidence of the injury being suffered by the petitioners caused by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti dumping investigation.

Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 01.01.2013 to 31.12.2013 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the periods from April 2010-March 11, April 2011-March 2012, April 2012-March, 2013 and the POI.

Submission of information

13. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

19. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

24. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority